# कृषि राजस्व बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण

सैकत सरकार

भारत में, कृषि न केवल देश की जीडीपी में 19 प्रतिशत योगदान देती है बल्कि लगभग आधी जनसंख्याकी आजीविका का समर्थनभी करती है।

साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के वर्तमान आह्वान में खाद्य प्रसंस्करण का भारत में एक महती भूमिका निभा सकता है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र ने कृषि, विनिर्माण क्षेत्र और अंतिम उपभोक्ताओं के बीच सशक्त संबंध स्थापित किए हैं तथा मूलभूत के निर्माण के से फसल की कटाई के बाद की हानि को कम भीकिया है। प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कृषि उपज में महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन किया है। प्रसंस्करण द्वारा किया गया मूल्य संवर्धन, मूल्य श्रृंखला में हानियों की रोकथाम करके किसानों के पास वापस आता है, तो उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

अगले 10 वर्षों तक, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र निश्चित रूप से हजारों नौकरियां उत्पन्न करने के अलावा किसानों की आय बढ़ाने में सक्षम होगा (भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के समर्थन के साथ)। उनकी रिपोर्ट 'भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनलॉकिंग वैल्यू' के अनुसार 'जिसे फूडप्रो 2022 में14वें संस्करण के के रूप में प्रस्तुत किया गया था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अगले पांच वर्षों में 530 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की आशा है। नॉलेज पार्टनर के रूप में मैकिन्से एंड कंपनी भी इस विचार से सहमत थी।

कृषि क्षेत्र के पाँच साल के सीएजीआर 3.4 प्रतिशत की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 9.5 प्रतिशत की तीव्र गति से बढ़ा है। इसके आगे, यह क्षेत्र 15 प्रतिशत सीएजीआर के साथ 2024 तक 9 मिलियन नौकरियाँ प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इस प्रकार, यह क्षेत्र संभावित रूप से वह समाधान हो सकता है जिसकी भारत को किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आवश्यकता है।

उपरोक्त सभी आंकड़ों को छूने की संभावना अधिक है, यदि भोजन की बर्बादी को अनुकूलित करने, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने की दिशा में निरंतर ध्यान दिया जाए।

अतीत में, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने की नई विधियाँ प्रस्तुत करके, फसलों का अपेक्षाकृत अधिक मूल्य और सब्सिडी के माध्यम सेकृषि में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करके, और कृषि संस्थानों को सुविधाजनक बनाकर किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। यद्यपि इन प्रयासों से स्वतन्त्रता के बाद से हमारी कृषि उपज में 3.7 गुना की वृद्धि हुई है, लेकिन इससे किसानों की आय में कोई

https://doi.org/10.52151/aet2023473.1676





विषेश वृद्धि नहीं हुई है। अधिकांश किसानों (छोटे और सीमांत – सभी किसानों का 82 प्रतिशत हिस्सा) ने अभी भी अपनी आय में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी है। मूल्य श्रृंखला के सबसे निचलेस्तर पर स्थित किसान के पास सौदेबाजी की शक्ति नहींहोने के कारण, इनको फसल के बाद भंडारण और परिवहन में होने वाली हानियों के अतिरिक्त प्रसंस्करण सुविधाओं आभाव में अधिक हानि उठानी पड़ती है।

विश्व स्तर पर सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उच्च स्तर के प्रसंस्करण (भारत में 10 प्रतिशतकी तुलना में 70–80 प्रतिशत ) और कृषि में प्रति श्रमिक उच्च मूल्य वर्धित उन्नत खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थिति की तंत्र है। भारत, कई कृषि वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद, कृषि में प्रति श्रमिक मूल्यवर्धन के मामले में कई देशों से पीछे है।

भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों से कृषि क्षेत्र की तुलना में प्रति कर्मचारी बहुत अधिक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) उत्पन्न किया है। प्रति कर्मचारी यह बढ़ी हुई जीवीए, मूल्य श्रृंखला के प्रमुख कड़ी, किसानों को वितरित की जाये तो उनकी संभावित कमाई में वृद्धि हो सकती है।

इस प्रकार, हमारे लिए समय की माँग है कि हम खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कृषि में अधिक मूल्यसंवर्धन की दिशा में अपने कदम को तेज करें।

इसे पूरा करने के लिए, छोटे और सीमांत किसानों को खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करना होगा, उत्पादक के रूप में नहीं बल्कि प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे उद्यमियों के रूप में जो इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

कुछ ऐसी ही निम्नलिखित खाद्य प्रसंस्करण विधियाँ अपना कर किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेगा.

कुशल भंडारण और परिवहन के माध्यम से फसल कटाई के बाद की हानि में कमी.

वैश्विक स्तर पर 28 प्रतिशत की तुलना में भारत में कुल खाद्य बर्बादी में कटाई के बाद पारगमन में बर्बादी लगभग 40 प्रतिशत होती हैए और इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में महत्वपूर्ण कमी आती है। इसका प्रभाव फलों और सब्जियों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों पर अधिक पड़ता है, जिससे किसान लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाएं किसानों को लंबे समय तक भोजन को संरक्षित करके इन नुकसानों को कम करने में सहायता करती हैं। इससे कीमतें अधिक होने पर फसल का मुद्रीकरण भी संभव हो जाता है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, भंडारण और परिवहन सुविधाएं सुलभ और सस्ती होनी चाहिए। साझा बुनियादी ढांचे के साथ क्लस्टर दृष्टिकोण सफलता का एक ऐसा मॉडल प्रदर्शित करता है।

फसलों का मूल्यसंवर्धनः कम मूल्य वाली फसलों के उत्पादन में लगे किसान उच्च मूल्य वाले प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण के माध्यम प्रसंस्कृत उत्पाद बनाकर मूल्य संवर्धन करके घरेलू आय बढ़ा सकते हैं। यह विश्व स्तर पर सिद्ध पद्धति है। कई अफ्रीकी देशों में, किसान ज्वार को बीयर या कसावा की गारी या स्नैक फूड में संसाधित करके बहुत सफल लघु–स्तरीय व्यवसाय स्थापित करते हैं। भारत में, प्रदर्शित उदाहरणों में पापड़, अचार और चटनी बनाना आदि सम्मिलित है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं सहित कई किसानों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत बन गए हैं। अधिक से अधिक किसानों को इस श्रृंखला में सम्मिलित तथा उत्पाद श्रृंखला का विस्तार करके, खेत के निकट कृषि प्रसंस्करण गतिविधियाँ कई किसानों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भारत सरकार ने अपनी कृषि–समुद्री प्रसंस्करण और कृषि–प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना (संपदा योजना) के तहत 63 से अधिक कृषि–प्रसंस्करण समूहों को मंजूरी दी है।

मूल्य श्रृंखला लिंकेज: किसान सीधे खाद्य निर्माताओं (द्वितीयक/तृतीयक प्रोसेसर) से जुड़ सकते हैं और अपनी उपज (ताजा/प्राथमिक उत्पादन) बड़े खाद्य निर्माताओं को बेच सकते हैं। तमिलनाडु में कृष्णागिरी क्लस्टर के किसानों से जुड़े एक नये अध्ययन से पता चला है कि जो किसान प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े हैं, वे गैर–प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले किसानों की तुलना में औसतन लगभग 49 प्रतिशत अतिरिक्त आय प्राप्त करने में सक्षम थे। खाद्य प्रसंस्करण की भविष्य की बाजार क्षमता से फसल उपज की अधिक माँग उत्पन्न होने की संभावना है, जिससे किसानों के लिए प्रसंस्करण योग्य प्रजातियोंके लिए एक नये बाजार का सृजन होगा। खाद्य प्रसंस्करण कंपनियाँ किसानों के साथ सीधे जुड़ाव के लिए आरम्भ से अंत तक की व्यवस्था कर सकती हैं, जिसमें उनकी शिक्षा को भी शामिल कर सकते हैं, जिससे उन्नत प्रौद्योगिकियों, प्रसंस्करण योग्य फसलों की खेती और उच्च मूल्य वर्धित उत्पाद लाइनों के निर्माण के विषय में किसानों के ज्ञान में वृद्धि होगी।

उपरोक्त सभी के साथ, उच्च उपज वाली फसल की प्रजातियों और निर्यात के अवसर, किसानों की आय पर धीरे–धीरे किन्तु सुनिश्चित प्रभाव डालेंगे।

कोविड–19 के बाद की दुनिया में उपभोक्ता बाजार में भी प्रसंस्कृत भोजन को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि से किसानों को बड़े उत्पादकों की मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने के अवसर पैदा होने की आशा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है कि लाभ इच्छित लाभार्थियों–छोटे और सीमांत किसानों तक पहुँचे। एक निरंतर और चुस्त नीतिगत हस्तक्षेप या कार्य योजना निश्चित रूप से 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के हमारे सपने के अनुरूप होगी और इसमें खाद्य प्रसंस्करण त्वरित योगदान करने में सक्षम है।